>

Title: Need to sanction funds for electrification of rural areas in Uttar Pradesh.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत सरकार के संज्ञान में एक लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं। जब हम सांसद अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो कोई 100 लोग मिलने आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सांसदों से 80 प्रतिशत लोग बिजली की मांग करते हैं। भारत सरकार ने 2005 में गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के तहत विभिन्न प्रदेशों में 100 से अधिक आबादी वाले गांवों और मजरों को स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश में 2004 में कई गांव और मजरे मुख्य योजना में शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की स्वीकृत योजना के अनुसार 100 से अधिक आबादी वाले 1,38,373 मजरों को विद्युतीकरण करने हेतु 12,367 करोड़ रुपए की योजना केन्द्र को भेजी थी। केवल रायबरेली और सुल्तानपुर के लिए 453 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, शेष आज तक बाकी है। भारत सरकार यह कह रही है कि 300 से अधिक आबादी पर योजना मांगी गई है प्रांतों से। केन्द्र सरकार ने 2012 तक प्रत्येक घर को बिजली देने की घोषणा की थी। लेकिन जब योजना ही स्वीकृत नहीं होगी तो विद्युतीकरण का काम कैसे पूरा होगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मजरों के विद्युतीकरण की योजना केन्द्र में जो लम्बित है, उसके लिए तत्काल राशि स्वीकृत की जाए ताकि हम लोग जो अपने पिछड़े इलाकों से जीतकर आए हैं, वहां के लोगों की बिजली की मांग पूरी कर सकें, जो देश की मूलभूत आवश्यकता है।